



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56750

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10331/2026

वीरेन्द्र पासवान उर्फ वीरेन्द्र राम एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : मुक्ति नाथ पाण्डेय, पशुपति नाथ पाण्डेय

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम

1. श्री पशुपति नाथ पांडेय, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, श्री प्रेम नारायण राय, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्तागण की एकमात्र शिकायत यह है कि 12.01.2024 को रेलवे दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णय द्वारा दावेदार/याचिकाकर्तागण के पक्ष में 80,000/- रुपये की राशि जारी करने का निर्देश दिया गया है, जो अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण और पूरी तरह से अपर्याप्त है। यह एक रेल दुर्घटना में वर्तमान याचिकाकर्तागण के बेटे की मृत्यु के लिए मुआवजा देने के उद्देश्य को विफल करता है।
3. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि 10.08.2018 को हुई एक रेलवे दुर्घटना में, याचिकाकर्तागण के बेटे रंजन कुमार को घातक चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्तागण ने 19.12.2018 को एक दावा याचिका दायर की। दुर्घटना की घटना के लगभग छह साल बाद 12.01.2024 को यह निर्णय लिया गया है। फिर भी, उस निर्णय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा, न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्तागण को 8,00,000/- रुपये (कुल मिलाकर) का आदेश दिया है।

4. न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्तागण को 80,000 रुपये जारी करने का प्रावधान किया है और शेष राशि को तीन साल की अवधि के लिए सावधि जमा में जमा किया जाना है।

5. याचिकाकर्ता यांत्रिक तरीके से जारी करने के लिए निर्देशित पूरी तरह से अपर्याप्त राशि से व्यथित हैं। दिए गए कुल मुआवजे को देखते हुए, वर्तमान में 80,000/- रुपये की राशि जारी की जाएगी, हालांकि याचिकाकर्तागण का दावा है कि 8,00,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता पूरी राशि जारी करने की प्रार्थना करते हैं।

6. दूसरी ओर, रेलवे के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि अनुपालन के नब्बे प्रतिशत को जारी करने पर रोक लगाने का आदेश केवल याचिकाकर्तागण के हित में है क्योंकि ब्याज अर्जित होने पर तीन साल के बाद उन्हें अधिक राशि मिलने की संभावना है।

7. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, जबकि ऐसे मामलों में सार्वभौमिक रूप से लागू सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, जहां अधिनिर्णय दिए जाने के समय आंशिक मुआवजा राशि जारी की जाती है और शेष राशि दावेदारों के लाभ के लिए निवेश की जाती है, एक ही समय में, इसे सभी मामलों में अंगूठे के नियम के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। इसमें, व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों को ऐसे मामलों में विवेक के प्रयोग को निर्धारित करना चाहिए। जिन दावेदारों ने अपने बेटे को खो दिया है और जिन पर कुछ निर्भरता का भी दावा किया जा सकता है, उन्हें मुआवजे का अधिनिर्णय अर्जित करने के लिए वर्षों तक मुकदमा चलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग करने के कारण उस मुआवजे को प्राप्त करने के लिए आगे के वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, जाहिरा तौर पर ऐसे दावेदार के हित में।

8. इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा लागू किए गए उपरोक्त सिद्धांत को व्यावहारिकता के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक उचित राशि जारी की जा सके।



9. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता मृतक के माता-पिता हैं। उन्होंने मुआवजे के अधिनिर्णय के लिए मृत्यु की घटना से लगभग छह वर्षों तक प्रतीक्षा की है। इस समय दिया गया मुआवजा भी अत्यधिक नहीं है, बल्कि 8,00,000/- रुपये की मामूली राशि है।

10. तदनुसार, दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में संशोधन किया जाएगा।

11. इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर आनुपातिक ब्याज के साथ प्रदान की गई राशि का 75% यानी 6,00,000/- रुपये याचिकाकर्तागण के पक्ष में जारी किया जाए। शेष राशि को तीन साल की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्चतम असर वाली सावधि जमा में निवेश और रखा जाएगा।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुपालन के अनुपालन में भुगतान की गई किसी भी राशि को इस आदेश के अनुसरण में जारी की जाने वाली राशि के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।

14. इसके अतिरिक्त, यह आदेश याचिकाकर्तागण के प्रतिकर में वृद्धि का दावा करने के अधिकार से स्वतंत्र रूप से पारित किया गया है, यदि वे ऐसा करना उचित समझें।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम)

19 मार्च, 2026

नितिका श्री.